27.5.2019 दैनिक झारखंड

स्वदेश

बी.कॉम. के लिए जीएसीसी सहित 3 को बनाया शहरी केंद्र

इंदौर ● स्वदेश समाचार

देअविवि द्वारा बी.कॉम के दूसरे सेमेस्टर एटीकेटी की परीक्षा के लिए शहर में एकमात्र जीएसीसी को परीक्षा केंद्र घोषित किया गया है। ऐसे ही सांवेर, मह, देपालपुर में भी केंद्र बनाए गए हैं।

विवि से प्राप्त जानकारी के अनुसार एटीकेटी परीक्षा जून 2019 में सम्मिलित होने के लिए यह केंद्र तैयार किए गए हैं। इसके अंतर्गत इंदौर में अक्षय एकेडमी, केके महाविद्यालय सहित इस्वा, सेंटपाल, संस्कार, जीएसीसी, वैष्णव वाणिज्य सहित 16 कॉलेजों के एटीकेटी के विद्यार्थी जीएसीसी में परीक्षा देने जाएंगे।

इसी प्रकार सांवेर, मह, देपालपुर में वहीं के सरकारी कॉलेजों को केंद्र बनाया गया है, जबकि पमव गुजराती वाणिज्य महाविद्यालय में एमवी खालसा, साफ्टविजन, मॉडर्न इंस्टीट्यूट, एलटीएस, चोइथराम, जैन श्वेताम्बर आदि 45 कॉलेजों के विद्यार्थी सम्मिलित होंगे। ऐसे ही मोतीतबेला स्थित जीडीसी में यहां सहित 8 कॉलेज के विद्यार्थी परीक्षा देने पहुंचेंगे।

आधा दर्जन भवनों पर सोलर पैनल लगाकर 70 फीसदी बिजली खर्च घटाएगा डीएवीवी

1.91 रुपए प्रति यूनिट पर मिलेगी बिजली, आईएमएस, स्कूल ऑफ कॉमर्स, कम्प्यूटर, इकोनॉमिक्स, जर्नलिज्म और आईआईटी की छतों पर लग रहे पैनल

श्रद्धा चौबे | इंदौर

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के आधा दर्जन संस्थान सोलर बिजली से रोशन होंगे। खंडवा रोड स्थित तक्षशिला परिसर में आईएमएस, स्कूल ऑफ कॉमर्स, कम्प्यूटर, इकोनॉमिक्स, जर्नलिज्म और आईआईटी की छतों पर 670 किलोवॉट क्षमता के सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। यह रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी (रेस्को) मॉडल पर काम करेंगे। मतलब विश्वविद्यालय को संयंत्र स्थापना पर होने वाला खर्च नहीं वहन करना होगा। वहीं उसे उत्पन्न बिजली भी कम दाम में उपलब्ध हो जाएगी।

हर महीने 25 से 30 लाख रुपए का खर्च

वर्तमान में सभी संस्थान को 7 से 8 रुपए (प्रति यूनिट) के हिसाब से बिजली मिल रही है। विश्वविद्यालय को हर महीने 25 से 30 लाख रुपए का बिल भुगतान करना होता है। चीफ वॉर्डन डॉ. अजय तिवारी के मुताबिक संयंत्र स्थापना के बाद विवि को 1 रुपए 91 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली मिलेगी। इससे

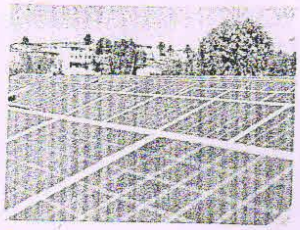

बिजली व्यय लगभग 70 फीसदी घट जाएगा। ग्रीन एनर्जी का फायदा नैक ग्रेडिंग में भी मिलेगा।

इसी सप्ताह काम हो जाएगा शुरू

सोलर संयंत्र स्थापना को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। एक सप्ताह में काम शुरू हो जाएगा और बिजली भी मिलने लगेगी। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने वाली प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी बन जाएगी। गौरतलब है कि इसी तर्ज पर भोपाल में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भी काम करने जा रहा है।

स्वदेश

शेष-विशेष

कॉलेजों की संबद्धता और सत्यापन 30 तक पूरा करने के निर्देश

इंदौर ● महाविद्यालयों की संबद्धता और पोर्टल पर सत्यापन 30 मई तक करना है, जिसके निर्देश उच्च शिक्षा विभाग ने देअविवि के कुलसचिव सहित अग्रणी महाविद्यालयों के प्राचार्य और वहां के एडी को भी जारी किए हैं। इन्हें कहा गया कि यूजी-पीजी में शीघ्र ही ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू होनी है इसलिए संबद्धता और सत्यापन का कार्य 30 मई तक किसी भी स्थिति में पूरा कर लिया जाए। चेतावनी भी दी गई है कि इसमें लापरवाही करने पर कार्रवाई की जाएगी।

विवि ने केंद्राध्यक्षों को दिए निर्देश

वीक्षकों के मोबाइल रहेंगे प्रतिबंधित

इंदौर ● स्वदेश समाचार

देअविवि द्वारा इंदौर से लेकर बुरहानपुर, खंडवा तक के समस्त कॉलेजों के केंद्राध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि परीक्षा के दौरान केंद्राध्यक्षों के मोबाइल बंद यानि प्रतिबंधित रखे जाए। ऐसा नहीं करने की स्थिति में कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है।

विवि की ओर से यह निर्देश इसलिए जारी किए गए हैं कि प्रश्न-पत्रों की गोपनीयता की दृष्टि से ऐसा किया जाना जरूरी है। दरअसल कक्ष में मोबाइल चालू होने की स्थिति में गोपनीयता भंग होती है और पूर्व में इस तरह की स्थिति में कई बार प्रश्न-पत्र आउट हो चुके हैं। इसे ध्यान में रखते हुए भी विवि के उपकुलसचिव ने कुलपति की ओर से यह आदेश इंदौर, धार, झाबुआ, खंडवा से लेकर आलीराजपुर आदि तक जारी किए हैं। स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस आदेश का सख्ती के साथ पालन कराया जाए, क्योंकि परीक्षा के दौरान निरीक्षण दलों द्वारा सघन निरीक्षण भी किया जाएगा। यदि गलती से इस दौरान किसी के पास मोबाइल मिला तो केंद्राध्यक्ष सहित शिफ्ट इंचार्ज और अन्य के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, जिसकी जवाबदारी संबंधित की होगी। इसलिए मोबाइल जमा कराने के बाद ही प्रश्न-पत्र वितरण का काम चालू किया जाए।

मूल दस्तावेज मिलने के बाद ही निजी कॉलेज को दिए जाएं

इंदौर ● उच्च शिक्षा विभाग ने देअविवि के कुलसचिव सहित हेल्प सेंटर वाले सरकारी कॉलेजों के प्राचार्यों को निर्देशित किया है कि सत्र 2019-20 में एनसीईटी के पाठ्यक्रमों में प्रवेश की कार्रवाई के अंतर्गत आवेदकों के मूल दस्तावेज प्राप्त होने के बाद भी आवंटित शासकीय महाविद्यालय को हस्तांतरित किए जाए। ज्ञात हो कि इसके अंतर्गत बीएड आदि पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाना है।